भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 709

07 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

पोषण सुरक्षा

709. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण योजना के माध्यम से श्रीअन्न का वितरण बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के बीच श्रीअन्न के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) देश में श्रीअन्न की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उन्हें वितरित किया जा सके। यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में चावल, गेहूं और मोटे अनाज की समग्र मात्रा निर्धारित की गई अधिकतम सीमा के अनुरूप है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं/चावल (जैसाकि राज्य द्वारा अनुरोध किया गया हो) की समान मात्रा के स्थान पर मोटे अनाज/मिलेट्स (श्री अन्न) का भी आवंटन किया गया है।

....2/-

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, मोटे अनाज की खरीद, आबंटन, वितरण और निपटान के लिए, राज्यों को किसानों से एमएसपी दर पर केंद्रीय पूल के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी तथा छह माइनर मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समस्त मात्रा को टीपीडीएस/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत वितरित किया जाता है।

(ग) से (ड.): उपभोक्ताओं के बीच मिलेट्स (श्री अन्न) के लाभ के प्रति जागरूकता पैदा करने के संबंध में निम्न पहल की गई थीं।

I. भारत के प्रस्ताव पर मार्च, 2021 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष (आईवाईएम) घोषित किया। आईवाईएम 2023 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न हितधारकों (केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, किसानों, स्टार्ट-अप्स, निर्यातकों, रिटेल व्यवसाय, होटल, भारतीय दूतावासों, आदि) की सक्रिय सहभागिता को अपनाने और भारतीय मिलेट्स (श्री अन्न) को विश्व स्तर पर पहचान देने का प्रयास किया है।

II. मिलेट्स (श्री अन्न) क्यूलिनेरी कार्निवाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम, शेफ कांफ्रेंस, किसान उत्पादक संगठनों की प्रदर्शनी (एफपीओएस), रोड शो, किसान मेला, अर्धसैनिक बलों के लिए शेफ का प्रशिक्षण, इंडोनेशिया और दिल्ली में आसियान भारतीय मिलेट्स (श्री अन्न) महोत्सव आदि के माध्यम से भारत में जी20 की अध्यक्षता के दौरान मिलेट्स (श्री अन्न) को प्रोत्साहित किया गया था।

III. आईआरएआई, पूसा परिसर में दिनांक 18-19 मार्च 2023 तक विश्व मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था।

....3/-

IV. 'श्री अन्न' के लिए भारत को एक वैश्विक हब बनाने के लिए, भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) हैदराबाद को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा किया जा सके। आईआईएमआर हैदराबाद द्वारा किसानों, महिला किसानों, गृहिणियों, छात्रों और युवा उद्यमियों को मिलेट्स (श्री अन्न) के मूल्यवर्धित खाद्य पदार्थों, दैनिक व्यंजनों आदि को पकाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है और उन्हें स्वयं के उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान की जा रही है।

IV. मिलेट्स (श्री अन्न) को मुख्य धारा में लाने के लिए दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली, में एक 'मिलेट्स इक्सपिरिएंस सेंटर (एमईसी)' खोला गया था ताकि मिलेट्स (श्री अन्न) के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और आम जनता को इसे अपनाने को लेकर प्रोत्साहित किया जा सके।

VI. सरकारी कर्मचारियों के बीच श्री अन्न के उपभोग को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने विभागीय प्रशिक्षणों/बैठकों में श्री अन्न युक्त नाश्ता शामिल करें और विभागीय कैंटीनों में श्री अन्न की खाद्य सामाग्रियों को शामिल किया जाए।

मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने हेतु, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख में पोषण युक्त अनाज (मिलेट्स) पर एक उप-मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए लचीला बनाया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से आरकेवीवाई के तहत राज्यों द्वारा मिलेट्स (श्री अन्न) को बढ़ावा दिया जा सकता है।

*****